कानपुर, शनिवार, 07 मार्च, 2026
वर्षः 03, अंकः 61, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड PSC:कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद निकले नए सितारे...>Pg12

सांसद, डीएम पर भारी अपर नगर आयुक्त का रुतबा!..>Pg03

मूल्यः 2 ₹

राजस्थान में सुबह भूकंप के झटके सीकर समेत कई इलाकों में हिली धरती

रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता दर्ज, जयपुर से करीब 69 किमी उत्तर-पश्चिम रहा केंद्र, कोई जनहानि नहीं

स्वराज इंडिया ब्यूरो

जयपुर/सीकर। राजस्थान में शनिवार सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में घबराहट फैल गई। सुबह करीब 6:30 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप का सबसे ज्यादा असर सीकर जिले और उसके आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। हालांकि झटके हल्के होने के कारण कहीं से भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए। कुछ सेकेंड बाद ही स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन की ओर से भी किसी बड़े नुकसान या हादसे की पुष्टि नहीं की गई है। भूकंप की जानकारी देते हुए नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि इसका केंद्र जयपुर से लगभग 69 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिशा में था। भूकंप की गहराई जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार कम गहराई पर केंद्र होने के कारण आसपास के इलाकों में कंपन अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से महसूस हुआ।

जानकारी के मुताबिक सीकर जिले के कई क्षेत्रों में धरती हिलने का अहसास हुआ। खाटूश्यामजी, पलसाना, धींगपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने हल्का कंपन महसूस किया। स्थानीय लोगों के अनुसार कंपन करीब एक से दो सेकेंड तक रहा। पलसाना क्षेत्र के कई लोगों ने बताया कि झटकों के दौरान घरों के दरवाजे और खिड़कियां हल्की-हल्की हिलने लगीं। अचानक हुए कंपन से लोग कुछ देर के लिए घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप का असर बेहद हल्का था और कुछ ही क्षणों में स्थिति सामान्य हो गई।

भूकंप जोखिम नक्शे में जयपुर हाई रिस्क जोन में

करीब तीन महीने पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने देश का नया भूकंप जोखिम नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में जयपुर, अलवर और भिवाड़ी को उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। हाई रिस्क जोन का अर्थ है कि इन इलाकों में भविष्य में 5 से 6 तीव्रता तक के भूकंप आने की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि सीकर जिले को सीधे तौर पर इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जयपुर के निकट होने के कारण यहां भी कभी-कभी हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम तीव्रता वाले भूकंप आमतौर पर बड़े नुकसान का कारण नहीं बनते, लेकिन ऐसे झटके यह संकेत देते हैं कि क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां सक्रिय हैं। इसलिए भवन निर्माण में भूकंपरोधी मानकों का पालन करना जरूरी है।

कंपन के साथ अजीब आवाजें सुनी गईं

कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि झटकों के साथ अजीब तरह की आवाजें सुनाई दीं। लोगों का कहना है कि यह आवाजें मानो जमीन के भीतर से आ रही थीं। भूकंप विशेषज्ञों के अनुसार जब धरती की परतों में अचानक हलचल होती है तो चट्टानों के आपस में रगड़ने से कंपन के साथ हल्की आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं। यह सामान्य भूकंपीय प्रक्रिया का हिस्सा होता है और हल्के भूकंप के दौरान कभी-कभी ऐसा अनुभव लोगों को होता है।

एक नजर में

- शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके
- रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता दर्ज
- केंद्र जयपुर से 69 किमी उत्तर-पश्चिम, गहराई करीब 5 किमी
- सीकर, खाटूश्यामजी, पलसाना और आसपास के क्षेत्रों में महसूस हुआ कंपन
- झटके 1-2 सेकेंड तक रहे, कोई जनहानि या नुकसान नहीं
- कुछ लोगों ने कंपन के साथ अजीब आवाजें सुनने का दावा किया

रसोई गैस महंगी: घरेलू सिलेंडर 60 और कमर्शियल 115 रुपये तक बढ़े

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नई दिल्ली। देश भर में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में शनिवार 7 मार्च से बढ़ोतरी कर दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपये तक और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में करीब 115 रुपये की वृद्धि की गई है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

सूत्रों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय हालात और पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव, विशेषकर ईरान से जुड़े हालात के कारण ऊर्जा बाजार में दबाव बढ़ा है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। करीब 11 महीने बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। मुंबई में यह 852.50 रुपये से बढ़कर 912.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये तक पहुंच गई है।

➪ करीब 11 महीने बाद एलपीजी कीमतों में इजाफा, होटल-रेस्टोरेंट और आम उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर पड़ेगा। रसोई गैस महंगी होने से घरेलू खर्च बढ़ने की आशंका है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने-पीने की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। सिंगल सिलेंडर कनेक्शन वाले उपभोक्ता अब 21 दिन से पहले दोबारा बुकिंग नहीं करा सकेंगे, जबकि डबल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 25 दिन का अंतराल अनिवार्य कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में तेजी बनी रहती है तो आने वाले समय में गैस और ईंधन की कीमतों पर और दबाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं के साथ छोटे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।

कानपुर में घूसखोर लेखपाल आलोक दुबे बर्खास्त

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर। कानपुर में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लेखपाल आलोक दुबे को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जांच में सामने आया कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 41 संपत्तियां अर्जित कर ली थीं। मामले में कई बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी सामने आई है।

मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए आलोक दुबे की अपील को खारिज कर दिया और उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की हालिया समीक्षा बैठक के अगले ही दिन की गई, जिसे प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह मामला उस समय सामने आया जब आलोक दुबे राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत था।

➪ विभागीय जांच में 50 करोड़ से अधिक की 41 संपत्तियों का हुआ खुलासा

उस दौरान वह भूमियों के क्रय-विक्रय के कारोबार में संलिप्त पाया गया। जांच में पता चला कि उसने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए जमीनों की खरीद-फरोख्त में हेराफेरी की और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की।

मामले में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कराई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर एक समिति गठित कर पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान आलोक दुबे के पास करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 41 संपत्तियों का पता चला। इनमें कई संपत्तियां बेनामी होने की आशंका भी जताई गई।

कानपुर की होली का ऐतिहासिक उत्सव

आजादी के दीवानों की यादों के रंग में रंगा 'गंगा मेला'

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर का ऐतिहासिक गंगा मेला केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की यादों और शहर की सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। होली के बाद अनुराधा नक्षत्र के दिन तक (लगभग सात दिन) चलने वाली यह अनूठी परंपरा शहर को आज भी उसी उत्साह से जोड़ती है, जिस भावना के साथ इसे आज़ादी की लड़ाई के दौर में मनाया गया था। इस मेले का केंद्र रज्जन बाबू पार्क हटिया व सरसैया घाट होता है, जहां हजारों लोग गंगा किनारे एकत्र होकर रंग खेलते हैं, गले मिलते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। माना जाता है कि इस परंपरा को व्यापक रूप से पहचान वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कानपुर के लोगों ने विरोध के प्रतीक के रूप में सात दिन तक होली मनाई थी। हटिया मेला कमेटी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र बिश्नोई व महामंत्री विनय सिंह के मुताबिक यह गंगा मेला 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। उस समय कानपुर का हटिया बाजार क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहां व्यापारियों और युवाओं में राष्ट्रीय चेतना प्रबल थी। होली के अवसर पर हटिया क्षेत्र के रज्जन बाबू पार्क में रंग खेलने का आयोजन होता था। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने वहां रंग खेलने पर रोक लगाने की कोशिश की। स्थानीय व्यापारी गुलाब चंद्र सेठ ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के विरोध में शहर के कई प्रमुख लोग सामने आए, जिनमें जागेश्वर त्रिवेदी, पंडित मुंशीराम शर्मा 'सोम', रघुबर दयाल, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', श्यामलाल गुप्त 'पार्षद', बुद्धूलाल मेहरोत्रा और हामिद खान जैसे नाम शामिल थे। अंग्रेजी प्रशासन ने इन सभी को साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर कोतवाली में बंद कर दिया।

स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैलते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए और नागरिकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। कानपुर के व्यापारियों, कर्मचारियों, लेखकों और आम नागरिकों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। बढ़ते दबाव और जनआक्रोश को देखते हुए अंग्रेज अधिकारियों को अंततः गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करना पड़ा।

जब सभी स्वतंत्रता सेनानी अनुराधा नक्षत्र के दिन जेल से रिहा हुए तो शहरवासियों ने इसे अपनी जीत के रूप में मनाया। हटिया से रंगों से भरा ठेला निकाला गया और पूरे शहर में रंग खेलते हुए जुलूस निकला। इसके बाद सरसैया घाट पर एक विशाल उत्सव आयोजित हुआ, जिससे बाद में अनुराधा नक्षत्र में गंगा मेला मनाने की परम्परा चल पड़ी।

1942 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी परंपरा, हटिया की होली से शुरू होकर सरसैया घाट पर रंगों और गले लग कर होता है समापन

हाईलाइट्स

- **शुरुआत की पहचानः** वर्ष 1942, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः** अंग्रेजों द्वारा होली खेलने से रोकने और क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध से जुड़ा
- **मुख्य केंद्रः** रज्जन बाबू पार्क हटिया बाजार की होली और सरसैया घाट का मेला
- **अवधिः** होली से शुरू होकर लगभग सात दिन तक उत्सव
- **विशेष दिनः** अनुराधा नक्षत्र (होली के लगभग पांचवें दिन)
- **मुख्य आयोजनः** रंगों की शोभायात्रा, जुलूस, गंगा स्नान और सामूहिक होली
- **विशेषताः** शहर में होली का उत्सव सात दिनों तक जारी रहता है
- **पहचानः** स्वतंत्रता संग्राम की यादों से जुड़ा अनूठा सांस्कृतिक पर्व

आज भी जीवंत है परंपरा

आज भी कानपुर में गंगा मेला पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन रंगों का ठेला की शुरुआत ऐतिहासिक रज्जन बाबू पार्क हटिया बाजार से होती है। रंगों का ठेला बिरहाना रोड, नयागंज, चौक सर्राफा समेत शहर के कई हिस्सों से गुजरते हुए रज्जन बाबू पार्क तक वापस पहुंचता है। इस दौरान जमकर रंग खेला जाता है। इसके बाद शाम को इसी पार्क में बच्चों के लिए बाल मेला भी लगता है। जहां बच्चे झूलों व अन्य खेलों का आनन्द उठाते हैं। शाम को ही सरसैया घाट पर विशाल गंगा मेला लगता है, जहां हजारों लोग गंगा किनारे एकत्र होकर रंग खेलते हैं और एक-दूसरे को होली की बधाई देते हैं। इस वर्ष भी शहर में 10 मार्च को गंगा मेला आयोजित होगा।

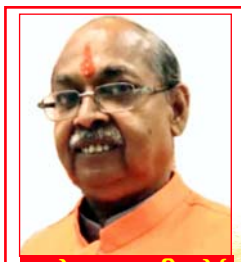

सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

ज्ञानेन्द्र कुमार विश्नोई
अध्यक्ष

विनय सिंह
महामंत्री

कानपुर का गंगा मेला केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शहर की ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम की भावना, व्यापारिक परंपरा और सामाजिक एकता का यह अनूठा संगम आज भी लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए है। रंगों, उत्साह और इतिहास से भरा यह मेला हर वर्ष लोगों को याद दिलाता है कि आज़ादी केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि जनभावनाओं और सामूहिक संघर्ष की कहानी भी है।

1942 की घटनाओं की टाइमलाइन

- **होली का दिनः** हटिया बाजार में क्रांतिकारियों और व्यापारियों ने अंग्रेजी आदेशों की अवहेलना कर होली खेली।
- **अंग्रेजी हस्तक्षेपः** एक अंग्रेज अधिकारी ने रंग खेलने से रोकने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने नकार दिया।
- **गिरफ्तारीः** गुलाब चंद्र सेठ सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों और व्यापारियों को गिरफ्तार कर सरसैया घाट कारागार में बंद किया गया।
- **शहर में विरोधः** गिरफ्तारी के विरोध में पूरे शहर के बाजार बंद हो गए और लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।
- **दबाव बढ़ाः** जनआक्रोश और विरोध के कारण अंग्रेजी प्रशासन पर दबाव बढ़ा।
- **रिहाईः** अनुराधा नक्षत्र के दिन सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया।
- **जश्न की शुरुआतः** हटिया से रंगों का ठेला निकाला गया और पूरे शहर में रंग खेलते हुए जुलूस निकाला गया।
- **गंगा मेला की परंपराः** सरसैया घाट पर उत्सव मनाया गया, जो आगे चलकर 'गंगा मेला' के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

सांसद, डीएम पर भारी अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव का रुतबा!

अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात जगदीश यादव पर लापरवाही पर कार्रवाई के लिए लिखे गए थे पत्र

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर।वैसे भी योगी आदित्यानाथ सरकार में ब्यूरोक्रेटस पर बेलगाम होकर कार्य करने के आरोप लगते रहते हैं। तमाम ऐसे मामले आए जिनमें अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही के चलते सरकार को जनता का आक्रोश झेलना पडा लेकिन अधिकारियों में सुधार की गुंजाइश फिर भी नजर नहीं आती। नगर निगम कानपुर में तैनात अपर नगर आयुक्त जगदीश यादव पर आरोप लगा कि डूडा-शासनस्तर से गठित जांच कमेटी में शामिल होने के बाद भी हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। इसपर डीएम और सांसद ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी, हालांकि अब मामला मैनेज हो चुका है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर न किए जाने के मामले में जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त से अभिमत मांगा था।

डूडा द्वारा जांच कमेटी में होने के बाद भी हस्ताक्षर करने से किया था इंकार, डीएम ने नगर आयुक्त को लिखा था कडा पत्र

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के निर्देश पर मामले की जांच के लिए त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई थी। इस समिति में अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. राजेश कुमार, तत्कालीन अपर नगर आयुक्त एवं परियोजना अधिकारी डूडा जगदीश यादव तथा कोषाधिकारी प्रांजल नगायच शामिल थे। समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच की गई और संबंधित कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। इसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी।

अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ. राजेश कुमार और कोषाधिकारी प्रांजल नगायच ने जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। हालांकि तत्कालीन अपर नगर आयुक्त एवं परियोजना अधिकारी डूडा जगदीश यादव ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए।

अपर जिलाधिकारी (नगर) ने 29 मार्च 2025 को जिलाधिकारी को भेजी गई अपनी आख्या में बताया था कि जगदीश यादव ने होली से पूर्व जांच रिपोर्ट का पुनः परीक्षण करने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा था। इसके बाद उन्हें कई बार दूरभाष के माध्यम से कार्यालय बुलाकर जांच पूर्ण कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने न तो कोई अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत किए और न ही अपना अलग मन्तव्य दिया। बाद में उन्होंने जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया।

इस आख्या के आधार पर जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त, नगर निगम एवं परियोजना निदेशक डूडा को पत्र लिखकर मामले में अभिमत मांगा था। जिलाधिकारी ने पत्र में कहा था कि जांच समिति के सदस्य होने के बावजूद रिपोर्ट पर हस्ताक्षर न करना शासकीय दायित्वों से बचने जैसा प्रतीत होता है।

डीएम ने नगर आयुक्त से 8 अप्रैल 2025 तक इस संबंध में अपना अभिमत उपलब्ध कराने तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, ताकि पूरी जांच रिपोर्ट राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ को भेजी जा सके।

ASHOK KUMAR RAWAT
MEMBER OF PARLIAMENT
LOK SABHA
Misrikh (U.P.)

MEMBER :
- Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food & Public Distribution
- Consultative Committee for Ministry of Petroleum and Natural Gas

6, Windsor Place, New Delhi-110001
B-21, Sector 'C', Aliganj, Lucknow - 226 024 (U.P.)
V/P - Shahpur Aliya, P.O. Sandila, Hardoi - 241 204 (U.P.)
Mobile : 9415047821, 9868180441

दिनांक - 1-5-2025

AMC-I

NA
02/05/25

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR
फोन नंबर (0512) 2304436, 2304287 ईमेल– dmkap@nic.in
पत्रांक-1959/एस0टी0/2025 दिनांक: 05.04.2025

नगर आयुक्त, नगर निगम/
परियोजना निदेशक, डूडा,
कानपुर नगर।

कृपया 'निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 6142/78/10/छ:/विविध/2022-23 XIII दिनांक 31/1/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत की गयी अनियमितता के संबंध में जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्कम में प्रकरण की जांच हेतु गठित समिति द्वारा जांच आख्या तैयार की गयी थी, परन्तु दिनांक 1/4/2025 तक तैनात रहे श्री जगदीश यादव, अपर नगर आयुक्त/परियोजना अधिकारी, डूडा, कानपुर नगर द्वारा अपर जिलाधिकारी(नगर), कानपुर नगर के साथ तैयार की गयी संयुक्त जांच आख्या पर हस्ताक्षर नही किये गये और ऐसा विदित होता है कि उनके द्वारा जानबूझ कर अपने शासकीय दायित्वों से बचा गया है। तत्कम में अपर जिलाधिकारी(नगर), कानपुर नगर की आख्या दिनांक 29/3/2025 अवलोकनीय है।

अतः कृपया प्रकरण के संबंध में अपने अभिमत से दिनांक 8/4/2025 तक अवगत कराने तथा संबंधित अपर नगर आयुक्त, नगर निगम के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार वांछित आख्या निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ को यथाशीघ्र प्रेषित की जा सके।

04.04.2025
(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

PA
Seek explanation of
AMC II - Jagdish Yadav

भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग के आरोप, सांसद ने मुख्यमंत्री से की थी कार्रवाई की मांग

कानपुर। कानपुर नगर निगम से जुड़े एक प्रकरण में अपर नगर आयुक्त (द्वितीय) और पूर्व परियोजना अधिकारी डूडा रहे जगदीश यादव पर भ्रष्टाचार और अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में सांसद अशोक कुमार रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सांसद द्वारा भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि जगदीश यादव ने डूडा में तैनाती के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कार्यों में लेखाकार एस.के. सिंह और सीएलटीसी के साथ मिलकर अनियमितताएं कीं। इसी कारण उन्हें उस पद से हटाया गया था। पत्र में बताया गया है कि जिलाधिकारी के आदेश पर गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति में सदस्य रहते हुए जगदीश यादव ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। समिति में अपर जिलाधिकारी (नगर) और कोषाधिकारी भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान कार्य मौके पर संतोषजनक पाए गए थे और जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के आधार पर डूडा अधिकारियों ने नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया पूरी की थी। आरोप है कि जांच समिति के सदस्य के रूप में जगदीश यादव ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत की मांग की। जब संबंधित पक्ष द्वारा धनराशि देने में असमर्थता जताई गई तो उन्होंने कथित तौर पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल शुरू कर दी और बाद में प्रतिशोध की भावना से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सांसद ने पत्र में यह भी कहा कि यह प्रकरण अधिकारियों को ब्लैकमेल करने और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि डूडा में अधिकांश स्टाफ आउटसोर्सिंग पर कार्यरत है और ऐसे में कामकाज की व्यवस्था भी उसी आधार पर संचालित होती है। सांसद ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पूर्व सीएलटीसी रवित रंजन की भूमिका भी संदिग्ध रही है। उनके अनुसार बिना किसी शिकायत के फाइलों को मुख्यालय भेजे जाने से पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े हो गए हैं सांसद ने कहा कि ऐसे मामलों से जिले की छवि धूमिल होती है और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का मनोबल भी प्रभावित होता है। उन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

उड़ान के बीच हेलिकॉप्टर में भरा धुआं

डिप्टी सीएम केशव मौर्य की इमरजेंसी लैंडिंग

लखनऊ से कौशांबी जा रहे थे उपमुख्यमंत्री, तकनीकी खराबी के बाद पायलट ने लिया तुरंत फैसला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए। लखनऊ से कौशांबी जाते समय उनके हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते केबिन के अंदर अचानक धुआं भरने लगा। स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत आपात स्थिति घोषित करते हुए हेलिकॉप्टर को वापस लखनऊ मोड़ दिया और सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई।जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लखनऊ से कौशांबी के लिए रवाना हुए थे। हेलिकॉप्टर ने जैसे ही ला मार्टिनियर ग्राउंड से उड़ान भरी,

तभी पायलट को तकनीकी गड़बड़ी का आभास हुआ। उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर के केबिन में धुआं भरने लगा, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और हेलिकॉप्टर को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की ओर मोड़ दिया। एयरपोर्ट पर पहले से ही सुरक्षा और आपात व्यवस्था तैयार रखी गई थी। इसके बाद हेलिकॉप्टर की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।लैंडिंग के बाद हेलिकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद तकनीकी विशेषज्ञों की टीम हेलिकॉप्टर की जांच में जुट गई है।

ताकि खराबी के कारणों का पता लगाया जा सके।

गली में भरा गंदा पानी, जिससे होकर गुजरती श्रद्धालुओं की भीड़

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मथुरा। श्रीबांकेबिहारी मंदिर में पीछे के आंगन में दूषित पानी भर गया। श्रद्धालु रेलिंग के बीच दूषित पानी में होकर निकले। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों के बीच चर्चा है कि मंदिर में नाली का दूषित पानी भर गया। इससे श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए।

शुक्रवार सुबह श्रीबांकेबिहारी मंदिर के पीछे के चौक में दूषित पानी भर गया। दूषित पानी में होकर श्रद्धालु रेलिंग के बीच से गुजरे। इसमें बच्चों और महिलाओं को सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल हो जाने क बाद श्रीबांकेबिहारी हाईपावर्ड कमेटी ने सफाई कार्य कराया।मंदिर के सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि मंदिर के पीछे के चौक में पहली बार ऐसा हुआ कि नाली का पानी भर गया। इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंध कमेटी ने सफाई कराई है।

कर्ज में डूबे 69 हजार किसान

बिजली बिल माफ़ योजना से बाहर

» उपभोक्ता पावर कॉरपोरेशन ऑफिस के काट रहे चक्कर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद । शासन और पावर कॉरपोरेशन ने किसानों को बिजली बिलों में 100न ब्याज में छूट दिए जाने की योजना शुरू की थी लेकिन जनपद के 69000 किसान उपभोक्ता इस माफ़ी योजना से वंचित रह गए हैं । आलू विपणन संघ निदेशक ने मुख्यमंत्री से इस माफ़ी योजना का समय बढ़ाए जाने की मांग की है लेकिन अभी तक समय न बढ़ने से किसान पावर कॉरपोरेशन ऑफिस के चक्कर काट रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से जनपद के आलू की घोर मंदी को देखते बिजली बिल छूट योजना को मार्च तक समय बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। आलू

विकास एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के निर्देशक अशोक कटिहार एडवोकेट ने कहा कि विगत 2 वर्ष से आलू किसान घोर मंदी के कारण गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है ।

कर्ज लेकर लगाई आलू की फसल से आय दोगुनी होना तो दूर किसानों को उनकी लागत भी नहीं निकल रही है, इस कारण बिजली बिल छूट योजना का समुचित लाभ लेने से बंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में 13571 उपभोक्ताओं में से 26 फरवरी 2026 तक 44600 उपभोक्ता माफी योजना का लाभ ले सके हैं करीब 69000 उपभोक्ता किसान धनाभाव के कारण योजना का लाभ लेने से बंचित रह गए हैं।

उन्होंने कर्ज में डूबे किसानों के समस्त बिजली बिल माफ ही नहीं बल्कि समय बढ़ाई जाएं। जिससे बिल माफ योजना का लाभ 69 हज़ार किसान लें सकें।

सम्पादकीय

कर्नाटक-आंध्र का सोशल मीडिया पर अंकुश

डिजिटल क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्य कर्नाटक ने सोलह साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बचाने के लिये देश में सबसे पहले अनुकरणीय पहल की है। राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि किशोरवय अब सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय अभिभावकों की उस चिंता को कम करता है जो अनियंत्रित डिजिटल गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम से परेशान थे। जिसमें साइबर बुलिंग व साइबर धोखाधड़ी भी शामिल है। कर्नाटक की पहल के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी विधानसभा में घोषणा की है कि अगले नब्बे दिनों के भीतर 13 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाएगी। इस तरह आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बाद ऐसा सख्त फैसला लेने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। इस प्रकार ये दो राज्य तेजी से ऑनलाइन होती दुनिया में 'किशोरों की सुरक्षा कैसे की जाए', की वैश्विक बहस में शामिल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसी पहल पहले आस्ट्रेलिया और फ्रांस आदि देशों में हो चुकी है। हालांकि, इन राज्यों की पहल सराहनीय है, लेकिन इस प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित होगा, इसका प्रारूप अभी स्पष्ट नहीं है। दरअसल, देश-दुनिया के मनोवैज्ञानिक और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग किशोरों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उल्लेखनीय है कि इस चिंता का जिक्र 2025-26 के केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया था। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की यह पहल तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य के प्रति एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण ही दर्शाती है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि इस कार्य योजना को अमलीजामा कैसे पहनाया जाएगा? यह हकीकत जानते हुए कि आज के डिजिटल युग में, स्मार्टफोन और ऐप्स शिक्षा, संचार और दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं।यहां उल्लेखनीय है कि तमाम स्कूल असाइनमेंट और अपडेट के लिये मैसेजिंग एप्स, ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता बढ़ गई है। यही वजह है कि छात्रों द्वारा 'शैक्षिक' और 'सामाजिक' उपयोग के बीच अंतर करना मुश्किल साबित हो सकता है। वहीं चिंता की बात यह भी कि किशोरों की आयु का सत्यापन कैसे व्यावहारिक बनाया जा सकेगा। वहीं देखना होगा कि सोशल मीडिया को संचालित करने वाली तकनीकी कंपनियां किस हद तक इस दिशा में सहयोग करेंगी। उन परिवारों में जहां एक ही मोबाइल फोन का परिवार के अन्य सदस्य भी उपयोग करते हैं, वहां प्रतिबंध की व्यावहारिकता पर सवाल लग सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया में पहले ही सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस जैसे अन्य देश भी सख्त डिजिटल सुरक्षा नियमों को लागू करने को लेकर गंभीर हैं।

इसमें दो राय नहीं कि बच्चों को बेहतर डिजिटल सुरक्षा दी जानी जरूरी है, लेकिन केवल नियमन मात्र से इस जटिल समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकता है। इस दिशा में सार्थक परिवर्तन सरकारों, स्कूलों, तकनीकी प्लेटफॉर्मों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अभिभावकों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। हालांकि, किशोरों को सोशल मीडिया की विकृतियों से बचाने के लिये तात्कालिक पहल केंद्र सरकार की तरफ से की जाती तो उसका देशव्यापी प्रभाव होता।

न्याय निष्पक्षता के महत्व की रक्षा हो

क्षमा शर्मा

न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान रखने के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि न्याय-व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति भी उसी समाज से आते हैं जिसका हम सब हिस्सा हैं। यह कौन कह सकता है कि हमारा समाज...न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान रखने के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि न्याय-व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति भी उसी समाज से आते हैं जिसका हम सब हिस्सा हैं। यह कौन कह सकता है कि हमारा समाज शत-प्रतिशत ईमानदार है?अब यह बात पुरानी नहीं बल्कि बहुत पुरानी लगती है।

सातवीं या आठवीं कक्षा में पढ़ता था मैं। सामूहिक गीत गवाये जाने की प्रथा थी तब स्कूल में। दो ऐसे गीतों की पंक्तियां मुझे आज, सत्तर-पचहत्तर साल बाद, भी याद हैं, अच्छी लगती थीं मुझे यह पंक्तियां। एक कविता में नया ज़माना लाने की बात कही गयी थीङ्क 'दे वरदान हमें माता हम निकले आन निभाने को... जहां बेटियां बिकती हैं, बेटों का मोल किया जाता... ऐसे समाज के ढांचे की हम निकले नींव हिलाने को...' और एक कविता थीङ्क 'मेरा देश कि जिसकी मिट्टी सोना उगले, और जहां की भूखी जनता मिट्टी निगले... न्याय दास है यहां करेंसी के नोटों का, शासन भिखमंगा है जनता के वोटों का..आज न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर देश में एक विवाद-सा चल रहा है। हुआ यह है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की आठवीं कक्षा की एक पुस्तक में देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक से एक पाठ शामिल किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस पर आपत्ति उठायी है। उन्हें लग रहा है कि आठवीं कक्षा के बच्चों को यह सब बताने से उनके कोमल मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। न्यायपालिका के बारे में उनके मन में गलत अवधारणा बन सकती है। तर्क यह दिया जा रहा है कि आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक की बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती कि वह मुद्दे की गहराई को समझ सके। न्यायालय ने आठवीं कक्षा की इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया है और एनसीईआरटी ने भी अपनी 'ग़लती' के लिए क्षमा मांग कर पुस्तक की बिक्री पर रोक लगा दी है। मैंने पुस्तक का यह विवादास्पद अध्याय नहीं पढ़ा है, पर इसके बारे में जितना कुछ मीडिया में आया है उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय को यह आशंका है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में दी गयी जानकारी से आठवीं में पढ़ने वाले बालक की बाल-बुद्धि पर गलत प्रभाव पड़ेगा। जब बाल-बुद्धि वाली यह बात मैंने पढ़ी तो अनायास मुझे वे दो कविताएं याद आ गयीं, जिनकी चर्चा आलेख के प्रारंभ में की गयी है। मैं सोच रहा हूं कि क्या सचमुच इन कविताओं को पढ़कर मेरे मन में 'जर्जर समाज' या 'करेंसी नोटों की दास न्यायपालिका' के बारे में कोई ऐसी धारणा बन गयी थी जिसे ग़लत कहा या समझा जा रहा है? सच कहूं तो आठवीं कक्षा की अपनी पढ़ाई के दौरान और आज उसके लगभग सत्तर साल बाद भी, और उस कविता को पसंद करने के बावजूद, न्यायपालिका के महत्व को मैंने कभी कम नहीं आंका, और न ही कभी मुझे ऐसा लगा कि न्यायपालिका के बारे में मेरे मन में सम्मान कहीं कम हुआ है।जिन चार स्तंभों पर हमारा जनतंत्र टिका है, उनमें संभवत- सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी न्यायपालिका और आरोपों और अपवादों के बावजूद आज भी न्यायपालिका पर देश का भरोसा कम नहीं हुआ है। न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल भले ही उठते रहे हों, पर इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुल मिलाकर हमारी न्यायपालिका देश की जनता को एक भरोसा देती है। यह भरोसा बना रहे शायद यही मंशा रही होगी उच्चतम न्यायालय की जब उसने एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की किताब के एक अध्याय पर सवालिया निशान लगाया।ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबों पर पहले कभी सवाल नहीं उठे। कई बार हुआ है ऐसा। कई बार इन किताबों में शामिल सामग्री विवादों के घेरे में आयी है। छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली यह किताबें हमारी भावी पीढ़ी का निर्माण करती हैं।

होली पर नवेली भौजाइयों को रंगने के लिए घेरने के उपाय

खो रहे होरी के पूर्वांचली रंग

निरंजन शुक्ला

होली के दिन पहले कच्चे बांस की खोखली नलियों से पिचकारी बनाई जाती थी। कोई-कोई ऐसा होता था, जिसके पास लोहे या पीतल की पिचकारी होती। अन्यथा ज्यादातर लोगों के पास बांस की पिचकारी होती, जिसका पंच किसी लकड़ी पर कपड़े लपेटकर बनाया जाता था। देसज बढ़ई इन पिचकारियों को तैयार करते थे।रहन-सहन में अब भी पारंपरिक देसज गंध से भरा है पूर्वांचल का इलाका। पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उससे सटा बिहार और झारखंड का इलाका। भारतीय नक्शे में इस इलाके में मोटे तौर पर भोजपुरी बोली जाती है।

यह इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के साथ ही बिहार के सारण मंडल के साथ ही मोतीहारी, चंपारण, आरा, बक्सर, सासाराम तक फैला हुआ है। वाराणसी और सासाराम से सटा हुआ है झारखंड का पलामू इलाका। यहां भी भोजपुरिया संस्कृति के रंग बिखरे हुए हैं। अब भी यहां के रहन-सहन, बोली-बानी में देसज भोजपुरिया मिठास भरी हुई है। लेकिन आधुनिक आर्थिकी के साथ यहां भी कुछ बदलाव आए हैं। शादी-विवाह, मुंडन-जनेऊ और अंतिम संस्कार में परंपराओं का पालन तो होता है, लेकिन उन पर बाजार का रंग अब पहले की तुलना में कहीं गहरे छा गया है। यही हाल यहां के पारंपरिक त्योहारों पर भी दिखने लगा है। पूरे देश में होली, रंग और उल्लास का त्योहार है। बासंती बयार के बीच दस्तक देने वाले इस त्योहार के वक्त समूचा देश रंगों में डूबता रहा है। लेकिन महानगरीय असर में अब रंगों की चमक और उल्लास कहीं खोती हुई नजर आ रही है। हास्य और लास्य का भी त्योहार है होली, लेकिन अब पूर्वांचल में हास्य की जगह फूहड़ता ने ले ली है, लास्य की लय भी कहीं खो गई है। अब पूर्वांचल का शायद ही कोई गांव बचा हो, जहां

पारंपरिक भोजपुरी रंग में फाग के राग सुनाई देते हों। कभी भंग के संग होली का रंग चढ़ता था, अब भांग की जगह आधुनिक अंगूर की बेटी ने ले ली है। चूंकि अंगूर की बेटी तक सबकी पहुंच नहीं, इसलिए सरकारी ठेके का पौव्वा आज की होली के उल्लास का सबसे बड़ा साथी नजर आ रहा है। पूर्वांचल में होली को फगुआ भी कहा जाता है। भोजपुरिया इलाके में आज से तीन दशक पहले तक लोग परदेस में नौकरी कर रहे लोग 'होली' की छुट्टी पर नहीं, 'फगुआ' की छुट्टी पर आते थे। जैसे ही खेतों में फसलें गोटाने लगती थीं, यानी उनके दानों का दूध गाढ़ा होकर अन्न का रूप लेने लगता था, बहरवांसु यानी बाहर कमाने गए लोगों के इंतजार की घड़ियां गिनी जाने लगती थीं। जब परदेसी कमासुत यानी कमेरा घर लौटता, घर ही नहीं, पूरे मोहल्ले में हर्ष की लहर दौड़ जाती थी। होली पर नवेली भौजाइयों को रंगने के लिए घेरने के उपाय सोचे जाने लगते, वहीं नवोढ़ा भाभियां भी देवरों पर आक्रमण का इंतजार करने लगतीं। देवर जी थोड़े भी लापरवाह हुए नहीं कि छपाक..और पूरा बदन भाभी के हाथों की मिठास भरे रंगों से सराबोर..पूर्वांचल में फगुआ का त्योहार महाशिवरात्रि के बाद से छिटफुट शुरू हो जाता था। किंचित अब भी होता है। लेकिन अब पहले जैसी गाढ़ी चाहत अब नहीं रही। हर उम्र की भाभियां अपने-अपने देवरों को रंगने की जुगत में जुट जाती थीं, इसके लिए वक्त की परवाह नहीं होती थी। रात का भोजन करते वक्त हर उम्र के देवर भौजाइयों के सबसे ज्यादा शिकार बनते थे..इसलिए उन दिनों कई लोग बेहद सावधानी बरतते थे..हालांकि सावधानी अक्सर हट जाती थी और रंग रूपी दुर्घटना का हमला हो जाता था।होली के दिन पहले कच्चे बांस की खोखली नलियों से पिचकारी बनाई जाती थी। कोई-कोई ऐसा होता था, जिसके पास लोहे या पीतल की पिचकारी होती। अन्यथा ज्यादातर लोगों के पास बांस की पिचकारी होती, जिसका पंच किसी लकड़ी पर कपड़े लपेटकर बनाया जाता था। देसज बढ़ई इन पिचकारियों को तैयार करते थे। लेकिन अब ये पिचकारियां बीते दिनों की बात हो गई हैं। अब प्लास्टिक ने घर-घर जगह बना ली है। पूर्वांचल में सवर्ण मोहल्लों की होली और दलित या मजदूर मोहल्लों की होली में किंचित अंतर होता था। दलित या मजदूर मोहल्ले से होली के मौसम में अच्छे-भले लोग गुजरने से परहेज करते थे। कारण यह कि कब ठाकुर साहब या पंडिजी की चमकती धोती पर गोबर या नाले का कीचड़ छपाक से आ गिरे, कोई गारंटी नहीं।

पुलिस की जाँच में नई बात आई सामने

..तो पहले से ही शादीशुदा था चांद बाबू उर्फ चंदू!

स्वराज इंडिया फालोअप

- ❍ पत्नी से संबंध ठीक न होने से एक साल से दोनों रह रहे थे अलग, नसिरापुर की युवती से करना चाहता था दूसरी शादी
- ❍ नाबालिग से शादी का दबाव बनाने पर उठाया कदम, फंसाने के लिए वीडियो में तीन लोगों के लिए थे नाम

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। जिस चाँद बाबू उर्फ चंदू ने बीते दिनों फांसी लगाकर मौत को गले लगाया, वह पहले से ही शादीशुदा था। आत्महत्या करने से पहले उसने 54 सेकेंड का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसमें उसने अपने गांव के इदरीस और आदिल तथा नसीरापुर के दीनू को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया था। अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन यादव ने बताया कि 5 मार्च 2026 को शाम करीब पांच बजे ग्राम रौगांव निवासी चाँद बाबू पुत्र सैयद (27) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी औरैया में रहती है। दोनों के संबंध ठीक न होने के कारण करीब एक साल से अलग-अलग रह रहे थे।

मृत्यु से पहले मृतक द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें उसने गांव के इदरीस और आदिल तथा नसीरापुर के दीनू को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक इदरीस और आदिल की भांजी तथा दीनू की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। युवती की उम्र नाबालिग होने के कारण उसके परिजनों ने शादी से इंकार कर दिया था। ये बात उसे नागवार लगी और इससे नाराज होकर उसने यह कदम उठा लिया और वीडियो में तीनों के नाम ले लिए। इंस्पेक्टर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वराज इंडिया
Swaraj India
06 Mar 2026 - Page 6
6 www.swarajindianews.com
कानपुर, शुक्रवार, 06 मार्च, 2026
बिल्हौर

..मेरी मौत के जिम्मेदार दीनू, छोटे और आदिल हैं!

प्रेम प्रसंग में युवती पक्ष से मिल रही धमकियों से आहत युवक ने फांसी लगाई

54 सेकेंड के वीडियो में बयां किया दर्द

नशे का भी आदी था चंदू

पत्नी से करीब एक साल से अलग रह रहा चंदू नशे का भी आदी बताया जा रहा है। लोगों की माने वह अक्सर शाम होते ही शराब के नशे में हो जाता था, जिससे घर में भी आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। सूत्रों की मानें तो आत्महत्या करने से पहले भी उसने शराब पी रखी थी। नशे और पारिवारिक तनाव के कारण वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहने लगा था।लोगों का कहना है कि उसका पिछले कुछ समय से उसका व्यवहार भी बदला-बदला सा नजर आ रहा था।

पत्नी से विवाद के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

- ➪ पत्नी शव से लिपटकर रोती रही, आधे घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही पैसेंजर ट्रेन

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। बिल्हौर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम पत्नी से कहासुनी के बाद एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पति का शव देखकर पत्नी बिलखने लगी और काफी देर तक ट्रैक से हटाने नहीं दिया, जिससे पैसेंजर ट्रेन करीब आधे घंटे तक वहीं खड़ी रही।

ढुलमऊ गांव निवासी जितेंद्र उर्फ मझिले (34) खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। शुक्रवार शाम वह बिल्हौर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ककवन रोड स्थित लक्ष्मी गेस्ट हाउस के सामने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उनकी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच कानपुर से फर्रुखाबाद की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद के दौरान ही युवक अचानक रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ा और ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। ट्रेन चालक ने युवक को ट्रैक पर देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह ट्रेन की चपेट में आ चुका था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद ट्रेन चालक और रेलवे कर्मचारियों ने शव को ट्रैक से हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान मृतक की पत्नी मौके पर पहुंच गई और पति का शव देखकर फूट-फूटकर रोने लगी। वह काफी देर तक शव को हटाने नहीं दे रही थी, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन करीब आधे घंटे तक वहीं खड़ी रही। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। बाद में अन्य परिजनों के पहुंचने पर शव को ट्रैक से हटाया गया, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में पत्नी और चार साल की एक बेटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जिलाधिकारी व एसपी ने रसूलाबाद पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं

- ➪ सम्पूर्ण समाधान दिवस के तहत सुनी फरियादें
- ➪ तहसील सभागार में तल्ख तेवर में दिखे डीएम

स्वराज इंडिया ब्यूरो

रसूलाबाद कानपुर देहात। जनपद के जिलाधिकारी कपिल सिंह व पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने रसूलाबाद पहुंचकर संपूर्ण समाधान दिवस में आए लोगों की शिकायतों को सुना और उन्हें गुणवत्ता पूर्वक निष्पक्ष ढंग से निस्तारित करने के आदेश दिए।

शनिवार को रसूलाबाद तहसील सभागार परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी कपिल सिंह ने की। वहीं जनपद के पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने भी शिकायतों को गंभीरता से सुना। समाधान दिवस में पहुंचे शैलेंद्र प्रताप सिंह पुत्र कृष्ण प्रताप निवासी बारनपुर कहिंजरी ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन लाला भगत में है सीमांकन राजस्व निरीक्षक के द्वारा किया गया था। 6 मार्च को प्रधान व उनके समर्थकों ने मेंड को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि वह वहां से तीस किलोमीटर दूर रहते हैं। मामले में उन्होंने आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। इसी प्रकार कनपटियापुर निवासी रोहित कुमार पुत्र प्रमोद कुमार ने बताया कि गांव में सरकारी नाली ब्लाक निधि से पास होकर बनाई जा रही है। जिसमें गांव के अनिल कुमार,विमल कुमार विकास कार्य के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोक रहे हैं। इन पर कार्रवाई करने की मांग की। कस्बा निवासी समाजसेवी यासीन परवेज ने बताया कि थाना और तहसील को जाने वाले दोनों मार्गों का चौड़ीकरण किया जाए ताकि जलभराव न हो। वहीं इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह की नीलम देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह, प्रीति देवी, संगीता निवासी तरौली जगमनपुर धीर ने बताया कि समूह की महिलाओं का आर्थिक रूप से शोषण बीएमएम नीरज सोनकर कर रहे हैं और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम इंदलपुर लालू क्लस्टर में जब से नीरज सुनकर आए हैं तभी से समूह की महिलाओं को समूह की धनराशि नहीं देते और समूह की महिलाओं से यह कहते हैं जैसा मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा नहीं करोगे तो मैं समूह से हटा दूंगा और समूह की महिलाओं को देर रात फोन करते हैं । वह कहते हैं ज्यादा कुछ करोगी तो तुमको समूह से हटा देंगे और समूह से पैसा भी नहीं निकलने देंगे। इस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी कपिल सिंह के आने की पहले से जानकारी होने के कारण फरियादी तहसील परिसर पहुंचे। संपूर्ण समाधान दिवस की कार्रवाई के दौरान कुछ एक मामलों में जिलाधिकारी का पारा गरम नजर आया। उन्होंने कहा कि ऐसा एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की नोटिस का कार्य जल्द पूर्ण करें और फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य शत प्रतिशत कराएं।

सपा विधायक की गैस एजेंसी से सिलेंडर चोरी का खुलासा, सात गिरफ्तार

गोदाम से चोरी हुए 43 सिलेंडर बरामद, देसी-अंग्रेजी शराब के 125 क्वार्टर भी मिले

स्वराज इंडिया ब्यूरो

चौबेपुर (कानपुर)। कस्बे में सपा विधायक की गैस एजेंसी के गोदाम से हुए सिलेंडर चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सात आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 43 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही विभिन्न ब्रांड की 125 क्वार्टर देसी व अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई है। सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

चौबेपुर कस्बे के बेला रोड स्थित सपा विधायक अमिताभ बाजपेई की एचपी गैस एजेंसी के गोदाम में 24 फरवरी की रात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश गोदाम से 127 भरे सिलेंडर, सात खाली सिलेंडर और तीन कॉमर्शियल सिलेंडर उठा ले गए थे।

अगली सुबह कर्मचारी जब गोदाम पहुंचे तो ताला टूटा देखकर घटना की जानकारी हुई। इसके बाद कस्बा निवासी शशिकांत पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। करीब एक सप्ताह की जांच के बाद पुलिस ने शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंहपोछा गांव निवासी आदित्य, मानपुर निवासी प्रांशु सिंह, उदेतपुर निवासी आर्यन तिवारी व प्रवीण तिवारी, दुबियाना निवासी आयुष कठेरिया, चौबेपुर थाना क्षेत्र के हिंदूपुर निवासी प्रांशु गौतम और तरियानी निवासी संतोष कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर चोरी के 43 गैस सिलेंडर और 125 क्वार्टर शराब बरामद की है। थाना प्रभारी के मुताबिक सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।घटना के खुलासे में एसआई शेर सिंह, रणवीर सिंह, सुभाष चंद्र मौर्य, अमित कुमार, विजय प्रकाश सिंह, पंकज मिश्रा, प्रदीप कुमार, पवन राजपूत, अमित सिंह राघव, रोहित त्रिपाठी, दीपक कुमार, योगेंद्र सिंह परिहार, हेड कांस्टेबल चंद्रकांत और सुनील कुमार शामिल रहे।

UPSC- कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद निकले सिविल सेवा के नए सितारे

रिजल्ट के साथ सामने आई संघर्ष और विवाद की अलग-अलग कहानियां

स्वराज इंडिया ब्यूरो

नई दिल्ली। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। लगभग एक वर्ष तक चली बहुस्तरीय परीक्षा प्रक्रिया के बाद जारी इस परिणाम में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

जारी अंतिम सूची के अनुसार कुल 958 अभ्यर्थियों को विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं में की जाएगी। यह परीक्षा प्रक्रिया अगस्त 2025 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा से शुरू हुई थी। इसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर फरवरी 2026 तक साक्षात्कार (इंटरव्यू) का दौर चला। हजारों उम्मीदवारों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी की

कठिन चयन प्रक्रिया

सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा के अंक और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम चयन केवल कुछ सौ उम्मीदवारों का ही हो पाता है। यही कारण है कि इसे देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है।

प्रशासनिक सेवाओं में नई पीढ़ी की एंट्री

इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब देश की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद विभिन्न सेवाओं में तैनात किया जाएगा, जहां वे नीति निर्माण, प्रशासनिक प्रबंधन और शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यूपीएससी का यह परिणाम एक बार फिर यह साबित करता है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और स्पष्ट लक्ष्य के साथ देश का कोई भी युवा इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा : एक नजर में

- **फरवरी - मार्चः** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी की जाती है और आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है।
- **मई - जूनः** प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) आयोजित की जाती है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और यह स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
- **जुलाई - अगस्तः** प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया जाता है।
- **सितंबर - अक्टूबरः** मुख्य परीक्षा (Mains) आयोजित होती है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं और कई विषयों पर विस्तृत उत्तर लिखने होते हैं।
- **दिसंबर - जनवरीः** मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होता है और चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
- **जनवरी - फरवरीः** दिल्ली में आयोग के मुख्यालय पर इंटरव्यू आयोजित किया जाता है।
- **फरवरी - मार्चः** अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है और मेरिट सूची जारी होती है।

संघर्ष की कहानीः "पुष्पेंद्र भइया"

इस बार के परिणामों के साथ एक ऐसी कहानी भी चर्चा में है, जो संघर्ष और धैर्य की मिसाल बन गई है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने वाले 48 वर्षीय पुष्पेंद्र पिछले लगभग तीन दशकों से सिविल सेवा का सपना देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से दिल्ली पहुंचे पुष्पेंद्र ने अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अद्भुत प्रयास किए हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं में मिलाकर 73 बार प्रारंभिक परीक्षा, 43 बार मुख्य परीक्षा और 8 बार इंटरव्यू तक का सफर तय किया है। हालांकि हर बार अंतिम चयन सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो सका। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। निजी जीवन की कई कठिन परिस्थितियोंपरिवार में असमय मौतें और पिता की कैंसर से लंबी बीमारी–के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उनके पिता की एक सीख "पढ़ने की कभी एक्टिंग मत करना"आज भी उनके लिए प्रेरणा बनी हुई है। यही कारण है कि मुखर्जी नगर में छात्र आज भी उन्हें सम्मान से "पुष्पेंद्र भइया" कहकर बुलाते हैं।

रिजल्ट के बाद नया विवाद

इस बार परिणाम के साथ एक रोचक विवाद भी सामने आया है। 301वीं रैंक को लेकर दो अलग-अलग युवतियों ने दावा किया है कि वही चयनित उम्मीदवार हैं। इनमें एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली आकांक्षा सिंह हैं, जबकि दूसरी बिहार के आरा की आकांक्षा सिंह बताई जा रही हैं। वाराणसी की आकांक्षा ने अपने दावे के समर्थन में एडमिट कार्ड और इंटरव्यू लेटर जैसे दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिनमें वही रोल नंबर दर्ज बताया जा रहा है जो परिणाम सूची में 301वीं रैंक के साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आरा की आकांक्षा ने भी खुद को उसी रैंक की सफल अभ्यर्थी बताया है, हालांकि उनके समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। इस विवाद ने प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में नई चर्चा शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों और कोचिंग संस्थानों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। फिलहाल इस मामले में अंतिम स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

सिविल सेवा परीक्षा क्यों खास

- इसे भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में माना जाता है, चयनित उम्मीदवार देश की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं

चयनित उम्मीदवारों की संभावित सेवाएं

- IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा), IPS (भारतीय पुलिस सेवा), IFS (भारतीय विदेश सेवा), IRS और अन्य केंद्रीय सेवाएं

परीक्षा में प्रतिस्पर्धा का स्तर

- हर साल लगभग 10-12 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, अंतिम चयन सामान्यतः 800-1000 उम्मीदवारों का ही होता है

तैयारी का प्रमुख केंद्र

- दिल्ली का मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर देश के प्रमुख सिविल सेवा तैयारी केंद्र माने जाते हैं

सफलता की कुंजी

- मजबूत वैचारिक समझ, लगातार अभ्यास और उत्तर लेखन, धैर्य और लंबे समय तक अनुशासित तैयारी

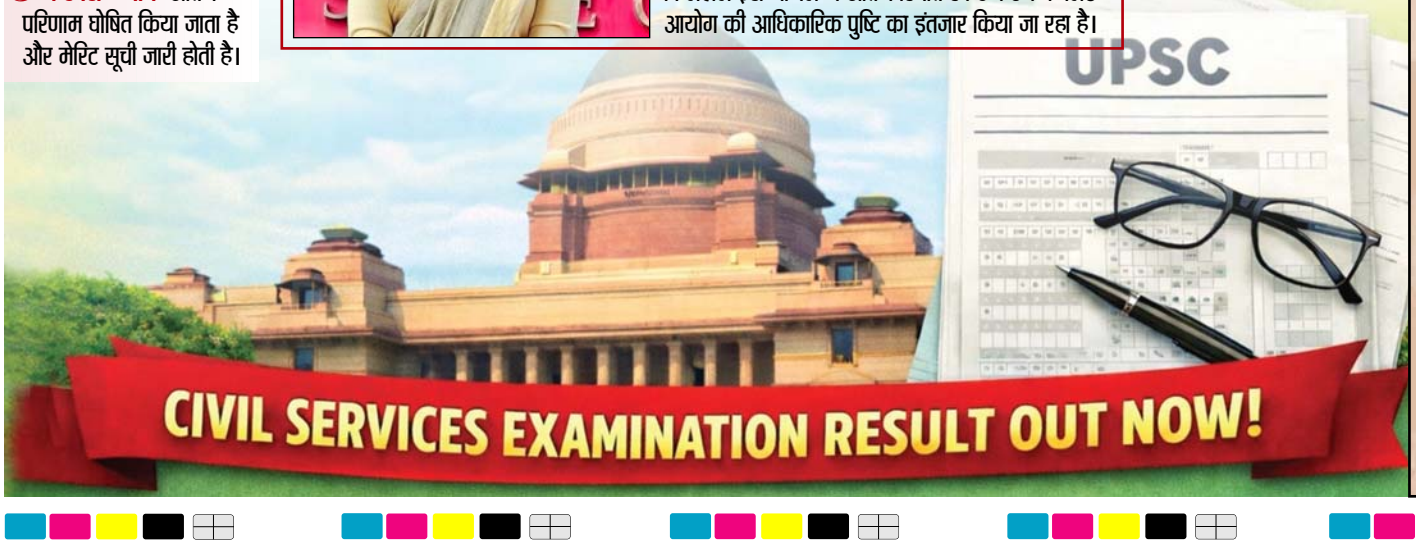

विजयईपुर गांव के बाहर धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी और बालू का खनन, जिम्मेदार बने मूकदर्शक

रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से हो रही खुदाई, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के विजयईपुर गांव के बाहर इन दिनों अवैध मिट्टी और बालू का खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।

रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से मिट्टी की खुदाई कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए उसे दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे हैं, जबकि जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार गांव के आसपास स्थित जंगलों से खाली पड़ी जमीनों से लगातार मिट्टी की खुदाई की जा रही है। देर रात तक जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिट्टी और बालू ढोने में लगी रहती हैं। इससे एक ओर राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारी वाहनों के लगातार आवागमन से क्षेत्र की सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध मिट्टी खनन और बालू का खनन कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस अवैध मिट्टी और बालू खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो गांव के आसपास की जमीनों में बड़े-बड़े गड्ढे हो जाएंगे, जिससे भविष्य में हादसों की आशंका भी बढ़ सकती है। इस सम्बन्ध मे उपजिलाधिकारी भोगनीपुर से सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है।

हिस्ट्रीशीटर चांद बाबू अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

» सट्टी पुलिस ने चेकिंग के दौरान तिराहे के पास दबोचा

कानपुर देहात। सट्टी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर हिस्ट्रीशीटर को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है।

पुलिस के अनुसार थाना सट्टी पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और वांछित आरोपियों की तलाश में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ग्राम अफसरिया के सामने सट्टी गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के तिराहे पर पहुंची। तभी सट्टी की ओर से पैदल आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। उसकी गतिविधि संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर करीब 100 मीटर दूर कच्चे रास्ते पर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम चांद बाबू उर्फ मोहम्मद पुत्र हारून कसाई निवासी ग्राम सट्टी थाना सट्टी बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। थानाध्यक्ष कालीचरण, उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार, हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह और कांस्टेबल अजय कुमार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

फांसी लगाकर युवक ने दी जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

एक दिन पहले से लापता था युवक, किसानों ने दी परिजनों को सूचना

रसूलाबाद, कानपुर देहात। थाना क्षेत्र के राना इटाहा गांव में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव तालाब के किनारे नीम के पेड़ से लटकता हुआ मिला। युवक ने गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार राना इटाहा गांव निवासी मंजीत (18) पुत्र अजय कुमार पढ़ाई करने के साथ-साथ बाहर नौकरी भी करता था। परिजनों ने बताया कि होली का त्योहार मनाने के लिए वह घर आया हुआ था और शुक्रवार को उसे वापस नौकरी पर जाना था। गांव के अन्य युवक काम पर चले भी गए, लेकिन मंजीत नहीं गया। बताया जाता है कि गुरुवार शाम करीब आठ बजे के बाद से मंजीत घर से लापता हो गया था। आसपास के क्षेत्रों में उसकी काफी तलाश की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। सुबह गांव के कुछ किसानों की नजर तालाब के किनारे खड़े नीम के पेड़ पर पड़ी, जहां एक युवक का शव गमछे के सहारे लटक रहा था। पास जाकर देखने पर पता चला कि शव मंजीत का है। किसानों ने तुरंत इस बात की सूचना उसके परिजनों को दी। घटना की सूचना मिलते ही रसूलाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

दुवारी में ग्राम समाज की 25 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर

खड़ी गेहूं-सरसों की फसल हटाकर कब्जा कराया मुक्त

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात माती। गजनेर क्षेत्र के दुवारी गांव में ग्राम समाज की भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर करीब 25 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया। इस दौरान खेतों में खड़ी गेहूं व सरसों की फसल पर जेसीबी चलवाकर जमीन खाली कराई गई। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली।

जानकारी के अनुसार दुवारी गांव की ग्राम प्रधान रेखा सिंह ने गाटा संख्या 156 की लगभग 25 बीघा ग्राम समाज की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर खेती किए जाने की शिकायत प्रशासन से की थी। शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग ने जांच कर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की।

शुक्रवार को नायब तहसीलदार विक्रम के नेतृत्व में गठित राजस्व टीम गजनेर, अकबरपुर और रनिया थानों की पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंची। प्रशासन ने तीन जेसीबी और तीन ट्रैक्टरों की मदद से खेतों में खड़ी सरसों व गेहूं की फसल हटवाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप की स्थिति रही और काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्राम समाज की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

वहीं, कब्जे के आरोपी पक्ष के गोपाल शुक्ला ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि उक्त भूमि उनकी पैतृक जमीन है, जिस पर उनकी कई पीढ़ियां खेती करती आ रही हैं। उन्होंने बताया कि यह जमीन पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम दर्ज थी, जिसमें उनके बाबा सदस्य थे। वर्ष 1980 में समिति से अलग होने के बाद जमीन उनके नाम दर्ज होनी थी, लेकिन गाटा संख्या गलत दर्ज होने के कारण विवाद खड़ा हो गया।

गोपाल शुक्ला का दावा है कि इस भूमि को लेकर मामला हाईकोर्ट और राजस्व परिषद में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व नोटिस के अचानक कार्रवाई कर दी, जिससे उनकी खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन पर बिजली कनेक्शन से संचालित नलकूप लगा हुआ है, जिसे बिजली विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण के बाद स्वीकृति दी गई थी। ऐसे में यदि जमीन ग्राम समाज की होती, तो नलकूप की स्वीकृति कैसे दी गई, यह भी जांच का विषय है। कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम में कानूनगो संतोष, अजय सिंह तथा लेखपाल सोनी सिंह और रमाकांत श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे, जबकि तीन थानों की पुलिस बल पूरी कार्रवाई के दौरान तैनात रहा।

अब सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों को नो एंट्री

» **रसूलाबाद व झींझक कस्बे में थी जाम की समस्या**

» **दिन में नो एंट्री लगने से व्यापारियों सहित कस्बावासियों को राहत**

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद तिराहा पर लगाई गई बेरिकेट

हलचल खबर का असर

रसूलाबाद कानपुर देहात। मुख्य चौराहा से निकलने वाले ट्रक व बड़े डंपर गाड़ियों के चलते चौराहों पर निकलना दूभर हो जाता था। दिन में निकलने वाले ओवरलोड डंपर व टेलर ट्रकों की आवाजाही के चलते भीषण जाम की समस्या खड़ी हो जाती थी जिससे जहां एक ओर यातायात बाधित होता था तो वहीं दूसरी ओर व्यापार पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता था। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय व्यापारियों ने जिम्मेदारों से समस्या बताई थी इसके साथ ही आपके लोकप्रिय सांध्य दैनिक अखबार स्वराज इंडिया ने भी इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद जनपद के जिलाधिकारी के निर्देश पर यातायात प्रभारी निरीक्षक ने दिन में सुबह 7=00 बजे से लेकर रात 10=00 बजे तक भारी वाहनों का कस्बे में प्रवेश वर्जित कर दिया । इसके साथ ही बनाए गए चेक पोस्ट में यातायात विभाग के दो आरक्षी सहित पीआरडी के जवान तैनात रहते हैं ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा सके। व्यापारियों सहित कस्बा वासियों ने प्रशासन के इस कार्य पर राहत की सांस ली।

जनपद के झींझक व रसूलाबाद कस्बे में दिन में भारी वाहनों के आवागमन से यातायात बाधित होता था। कस्बे में जाम की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। जिससे कस्बा वासियों का जीना दुश्वार हो रहा था। व्यापारी भी जाम की समस्या से त्रस्त आ चुके थे। उक्त समस्या को स्वराज इंडिया समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था इसके बाद खबर का असर देखने को मिला। जिसको लेकर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों तक बात पहुंची। जनपद के जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर रसूलाबाद व झींझक कस्बे में नो एंट्री लगाई गई। जनपद के सिकंदरा कस्बे में एक पुलिस चेक पोस्ट बनाई गई तो दूसरी रसूलाबाद कस्बे के झींझक रोड पर चेक पोस्ट बनाई गई है। जनपद के जिलाधिकारी कपिल सिंह व पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय के कार्यालय से जारी संयुक्त पत्र में बताया गया कि कोई भी भारी वाहन निर्धारित समय अवधि के अंदर कस्बे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल परमिट वाली बसें, परिवहन विभाग की गाड़ियां व आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को ही इस निर्धारित समय के बीच जाने-आने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन के इस कदम से काफी हद तक कस्बों में जाम की समस्या का हल निकलेगा हालांकि मुख्य चौराहों पर सवारी के लालच में ई रिक्शा व ऑटो चालकों के बीच चल रही होड़ से जाम की समस्या अभी इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। इसके साथ ही औरैया को जाने वाले लहरापुर मार्ग पर भी अभी भारी वाहनों का आवागमन जारी है। जिससे रसूलाबाद कस्बे की समस्या में इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली। स्थानीय व्यापारियों की माने तो औरैया मार्ग पर भी नो एंट्री लगनी चाहिए तब कहीं जाकर पूर्ण रूप से जाम से राहत मिलेगी।

स्वराज इंडिया
08
कानपुर देहात
जाम के झाम से मुसीबत में रसूलाबाद के वाशिंदे
मुख्य चौराहे से गुजरना बना चुनौती, ई-रिक्शा व ऑटो चालकों की मनमानी से हालात बदतर
» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
क्या बोले ईओ

गुरसहायगंज वन विभाग का कारनामा

हरे पेड़ो को उजाड़ कर जंगल मे एक किमी तक बना दिया अवैध रास्ता

जंगल को उजाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कन्नौज। गुरसहायगंज वन विभाग रेंज इन दिनों सुर्खियां बटोरने में लगा है। महकमें के कर्मचारियों ने दबंगो से मिलकर सरकारी जंगल मे अवैध मार्ग बना दिया । पूरा मामला रसूलपुर ऊँचा वन ब्लॉक जंगल का है जहाँ महकमे के दागियों की मिलीभगत के चलते इस कारनामे को अंजाम दिया गया।जंगल के बीच मे लगभग एक किलोमीटर तक बना दिया कच्चा अवैध मार्ग ।जंगल को उजाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इससे महकमे में हड़कंप मच गया । पर स्थानीय अधिकारी मामलों को दबाने में जुटे हैं। वायरल वीडियो की स्वराज इंडिया पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से बबूल के सरकारी जंगल को उजाड़ कर

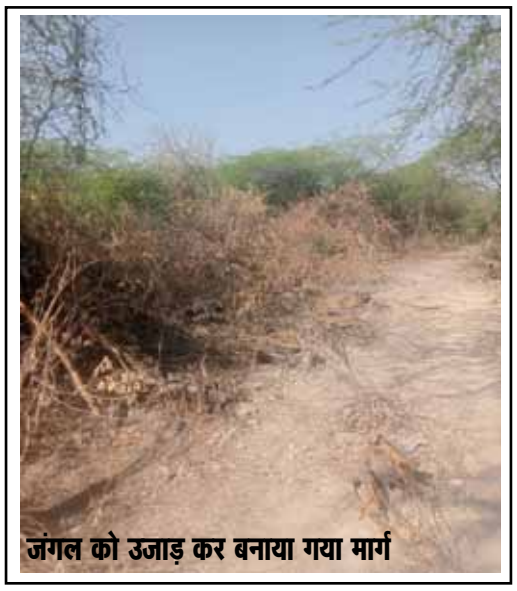
जंगल को उजाड़ कर बनाया गया मार्ग

यह कारनामा किया गया। सूत्रों की माने तो सेटिंग कर के यह हरे पेड़ो को उजाड़ कर रास्ता बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जा रहा था पर जब लोगो ने देखा तो कर्मचारी को लगा कि अब उसकी शिकायत हो जाएगी तब इसकी जानकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को दी गई । साथ ही बताया जा रहा कि कुछ कर्मचारी मौके पर पहुँचे भी और जेसीबी चलते हुए देखी लेकिन उसे छोड़ दिया गया । जंगल को उजाड़ कर रास्ता बनाने बालो पर व महकमे के रसूखदार दागियों पर भी कोई कार्यवाही नही की गई ।जिससे दागियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। डीएफओ हेमंत सेठ से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कोई जबाब नही दिया ।

अयोध्या मेडिकल कॉलेज में अचानक 'कुर्सी कांड'!

सीएमएस डॉ. अरविंद सिंह हटाए गए, अचानक हुई कार्रवाई चर्चा का विषय

राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक फैसले से मचा हड़कंप

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एक प्रशासनिक फैसले ने अचानक हलचल मचा दी है। कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ0 डी0 एस0 मर्तोलिया ने आदेश जारी करते हुए डॉ. अरविंद कुमार सिंह को सीएमएस पद से मुक्त कर शासन में योगदान देने के लिए रिलीव कर दिया। आदेश के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

बताया जा रहा है कि डॉ. अरविंद कुमार सिंह लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अचानक उन्हें पद से हटाए जाने से न सिर्फ अस्पताल स्टाफ बल्कि जनपद के स्वास्थ्य महकमे में भी हलचल है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यह फैसला अचानक सामने आया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग अब इस फैसले के पीछे की असली वजह तलाशने में जुटे हैं। फिलहाल डॉ. अरविंद कुमार सिंह के हटने के बाद मेडिकल कॉलेज में सीएमएस की कुर्सी को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है और यह मामला पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दो आईपीएस अधिकारी बंधेंगे वैवाहिक बंधन में

» 29 मार्च को बाड़मेर में होगा विवाह

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के दो युवा आईपीएस अधिकारी जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। संभल जनपद के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई और बरेली में एसपी सिटी के पद पर तैनात अंशिका वर्मा का विवाह 29 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में संपन्न होगा।

कृष्ण बिश्नोई मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी हैं।

जबकि अंशिका वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। दोनों अधिकारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ।परिवार के अनुसार विवाह समारोह बाड़मेर में सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी लोग शामिल होंगे ।पुलिस सेवा में सक्रिय रहते हुए दोनों अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा से अलग पहचान बनाई है। अब जीवन के नए अध्याय की शुरुआत को लेकर उनके परिवारों और परिचितों में खुशी का माहौल है।

रामनगरी में 'प्लॉट और पार्टनरशिप' का जाल!

» रेस्टोरेंट में 30त्न हिस्सेदारी और जमीन दिलाने का झांसा, महिला से वसूले 30.50 लाख

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। आस्था की राजधानी अयोध्या में जमीन और कारोबार के नाम पर ठगी का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक

30 लाख की ठगी में पांच पर मुकदमा

महिला से प्लॉट दिलाने और रेस्टोरेंट में पार्टनर बनाने का झांसा देकर करीब 30.50 लाख रुपये हड़प लिए गए। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शक्ति नगर कॉलोनी निवासी पीड़िता कविता गुप्ता के मुताबिक, उनकी मुलाकात परिचित अंतिम सिंह के जरिए अनुराग द्विवेदी से हुई थी। अनुराग ने उन्हें प्लॉट दिलाने का भरोसा दिलाया और 22 फरवरी से 12 अप्रैल 2024 के बीच उनकी बहन पूजा के खाते से शाकुंतलम डेवलपर्स के खाते में कुल 18.50 लाख रुपये जमा कराए।

इतना ही नहीं, बाद में अयोध्या राम मंदिर के पास स्थित प्रसादम रेस्टोरेंट में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी दिलाने के नाम पर उनसे 12 लाख रुपये और ले लिए गए। इसके लिए 25 सितंबर 2024 को बाकायदा एग्रीमेंट भी कराया गया।

पीड़िता के अनुसार मार्च 2025 में अनुराग द्विवेदी की मौत के बाद न तो प्लॉट मिला और न ही रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी।

जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। नगर कोतवाल अश्विनी पांडेय के अनुसार अनिल, शकुंतला, सूर्यांश द्विवेदी समेत शाकुंतलम डेवलपर्स व प्रसादम रेस्टोरेंट से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। रामनगरी में बढ़ते रियल एस्टेट और कारोबार के सपनों के बीच यह मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है क्या आस्था की नगरी में ठगी का नया कारोबार फल-फूल रहा है?

अयोध्या

रामनगरी में 'बिग-बी' का बिग दांव!

अयोध्या की जमीन पर 35 करोड़ का नया खेल

» तीसरी प्रॉपर्टी खरीदकर सुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने दिया बड़ा संकेत

» आस्था, रियल एस्टेट और अरबों की संभावनाओं का नया संगम बन रही

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अरबों के रियल एस्टेट खेल का नया अखाड़ा बनती जा रही है। इस बदलते परिदृश्य में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर बड़ा दांव खेल दिया है।

रियल एस्टेट कंपनी हाउस ऑफ अभिनंदन लोढा के प्रोजेक्ट के पास 2.67 एकड़ जमीन करीब 35 करोड़ रुपये में खरीदकर बच्चन ने साफ संकेत दे दिया है कि अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक राजधानी नहीं, बल्कि निवेश का नया गोल्डन जोन बन रही है। यह डील एबी कॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव के माध्यम से पूरी हुई।

दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में अमिताभ बच्चन की यह तीसरी प्रॉपर्टी है और लोढा ग्रुप के साथ उनका चौथा बड़ा निवेश। यानी रामनगरी की जमीन पर बिग-बी का भरोसा लगातार गहराता जा रहा है। कंपनी के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा का दावा है कि अयोध्या की जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि विरासत है। ऐसी विरासत जो आस्था और आने वाली पीढ़ियों की दौलत दोनों को जोड़ती है। दरअसल, मंदिर निर्माण, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और सरकारी निवेश के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उसने देश-विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित कर लिया है। अब सवाल यह है क्या अयोध्या आस्था की नगरी से आगे बढ़कर देश की सबसे महंगी आध्यात्मिक रियल एस्टेट राजधानी बनने जा रही है?

अदाणी फाउंडेशन के सीईओ ने किया रामलला का दर्शन

गोपनीय रखा गया लखटकिया का दौरा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। अदाणी फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डा. अभिषेक लखटकिया ने पत्नी शिवानी के साथ रामनगरी पहुंचे। राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन कर पूजन अर्चन किया। राम मंदिर पहुंचने के उनके कार्यक्रम के कार्यक्रम को लेकर गोपनीयता बढ़ती गई थी। सीईओ के लिए श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से विशिष्ट दर्शन पास जारी हुआ था। शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच का था। इसी में उन्होंने भगवान रामलला व राम दरबार में दर्शन व पूजन किया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राम मंदिर में दर्शन के बाद सीईओ लखनऊ के लिए रवाना हो गये। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी से उनके मिलने की जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि जिस तरह टाटा समूह राम मंदिर से लेकर मंदिर संग्रहालय के निर्माण में दिलचस्पी ले रहा है, कुछ उसी तरह का रुझान अदाणी समूह भी दिखा सकता है। लखटकिया दंपती का कार्यक्रम सिर्फ राम मंदिर तक ही सीमित रहा। जिला प्रशासन की तरफ से उनके विशिष्ट दर्शन पास आदि की व्यवस्था की गई थी। लखटकिया दंपती अहमदाबाद - गुजरात के निवासी बताये गए हैं।

चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार, 10 लाख के जेवरात बरामद

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नगर कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 10 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात व कीमती कपड़े बरामद किए हैं।

नगर कोतवाल अश्विनी पांडेय के अनुसार नवीन मंडी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जय किशोर अवस्थी व उपनिरीक्षक अखिलेश तिवारी की टीम ने उसरु नहर के पास मनीवीर स्कूल के निकट से नीरज यादव (30) निवासी परसवां शुकुल का पुरवा, थाना इनायतनगर को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने उसरू के वैष्णव नगर कॉलोनी तथा नवीन मंडी गेट के सामने स्थित एक किराना दुकान व आवास से जेवरात, नकदी और मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अंगूठी, चैन, झुमका, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल समेत कई आभूषण तथा ब्रीफकेस से साड़ियां और कपड़े बरामद किए। दोनों मामलों में पुलिस ने बरामदगी की धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी का चालान कर दिया है।

ईरान पर ट्रंप का कड़ा अल्टीमेटम, युद्ध के सातवें दिन बढ़ा वैश्विक तनाव

‘बिना शर्त आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता’

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। मध्य पूर्व में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। युद्ध के सातवें दिन ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और उसके सामने ‘बिना शर्त आत्मसमर्पण’ ही एकमात्र विकल्प है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान की ओर से कुछ देशों द्वारा संघर्ष समाप्त कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की बात कही गई थी। लेकिन वॉशिंगटन ने इन संकेतों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी वार्ता की संभावना नहीं है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि कई देश क्षेत्र में शांति स्थापित कराने के लिए मध्यस्थता करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका की नीति स्पष्ट है ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। उन्होंने लिखा कि यदि ऐसा होता है तो भविष्य में एक ‘बेहतर और स्वीकार्य नेतृत्व’ के चयन में मदद की जा सकती है और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान को आर्थिक रूप से स्थिर करने में सहायता देगा। ट्रंप पहले भी ईरान के नए सर्वोच्च नेतृत्व के चयन में अमेरिका की भूमिका की बात कर चुके हैं।

मध्यस्थता की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का सख्त रुख

खाड़ी में हमले तेज, तेल संकट और कूटनीतिक टकराव से दुनिया चिंतित

ईरान की तीखी प्रतिक्रिया

ट्रंप के इस बयान पर ईरान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत दौरे पर आए ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव भी अपनी इच्छा से नहीं करवा सकते, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता के चयन का सपना देख रहे हैं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका देश किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने देश की रक्षा कर रहा है और यदि अमेरिका जमीन पर सैनिक उतारने की कोशिश करता है तो उसका सामना किया जाएगा।

पश्चिम एशिया में हमले तेज

अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाइयों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी Beirut के दक्षिणी उपनगरीय क्षेत्रों में भारी बमबारी की है, जिन्हें हिज्बुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। दूसरी ओर ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। क्षेत्र में लगातार हो रहे हमलों के कारण नागरिक आबादी और व्यापारिक गतिविधियों पर भी गंभीर असर पड़ रहा है

तेल संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा

लगातार बढ़ते संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। खाड़ी क्षेत्र में हजारों तेल टैंकर फंस गए हैं, जिनमें भारत के भी लगभग 36 जहाज शामिल बताए जा रहे हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। फिलहाल अमेरिकी कच्चा तेल दो वर्षों में पहली बार 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है। शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी और आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागीं। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शुरू कर सकता है। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को 15.1 करोड़ डॉलर के नए हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है।

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के लिए बिना शर्त आत्मसमर्पण ही विकल्प
- ईरान ने दबाव में झुकने से किया इनकार, कहा देश की रक्षा जारी रहेगी
- अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत IRIS Dena डूबा, 100 से अधिक नौसैनिकों की मौत
- श्रीलंका ने 200 से अधिक ईरानी नाविकों को सुरक्षित उतारा, अमेरिका ने वापस न भेजने की अपील की
- खाड़ी में तेल टैंकर फंसे, कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार
- विशेषज्ञों की चेतावनी, संघर्ष लंबा चला तो तेल 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है
- रूस पर ईरान को खुफिया मदद देने के आरोप, अंतरराष्ट्रीय तनाव और गहरा हुआ

रूस की भूमिका भी चर्चा में

इस युद्ध में रूस की भूमिका भी अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस ने ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई है जिससे वह क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। रूस के राष्ट्रपति ब्लादमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशिकयान से फोन पर बातचीत कर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत पर संवेदना भी व्यक्त की है। लगातार बढ़ते सैन्य हमलों, ऊर्जा संकट और कूटनीतिक टकराव के बीच फिलहाल इस युद्ध के जल्द समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि स्थिति इसी तरह बनी रही तो इसका असर न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और सामरिक स्थिति पर गहराई से पड़ेगा।

हिंद महासागर में नई कूटनीतिक तनातनी

मध्य पूर्व के युद्ध के बीच अब हिंद महासागर में हुई सैन्य कार्रवाई ने एक नया कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत IRIS Dena को डुबोने की घटना के बाद अमेरिका ने Sri Lanka सरकार पर दबाव बनाया है कि वह बचे हुए ईरानी नाविकों को वापस ईरान न भेजे। बताया गया है कि श्रीलंका के तट से लगभग 19 समुद्री मील दूर इस युद्धपोत पर टॉरपीडो हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई, जबकि 32 को जीवित बचा लिया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेगसेथ ने इस हमले को "शांत मौत" की संज्ञा देते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरह की कार्रवाई बहुत कम देखने को मिली है। इस बीच ईरान के एक अन्य नौसैनिक सहायक पोत आईआरआईएस बुशहर के 208 चालक दल के सदस्यों को श्रीलंका ने सुरक्षित उतारना शुरू कर दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति एनुरा कुमारा दिशनाएके ने कहा कि संकट में फंसे नाविकों को सहायता देना उनके देश की मानवीय जिम्मेदारी है।

86 लाख से अधिक लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए किया आवेदन

यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण

- 3 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम हटाने की दी अर्जी, दावे-आपत्तियों की अवधि समाप्त
- 27 मार्च तक होगी सुनवाई, 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम सूची

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-SIR) के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नाम जोड़ने और हटाने के लिए आवेदन किया है। चुनाव विभाग के अनुसार अब तक 86 लाख से अधिक लोगों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, जबकि तीन लाख से अधिक लोगों ने सूची से अपना नाम हटाने के लिए अर्जी दी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। शुक्रवार को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई। अब अगले चरण में इन आवेदनों की सुनवाई की जाएगी और जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान 1.66 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया, जबकि 7,329 लोगों ने फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने का अनुरोध किया।

चुनाव आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद से 6 मार्च तक कुल 70,69,810 लोगों ने फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा 2,642 लोगों ने फॉर्म-6 (ए) भरा है। इसी अवधि में 2,68,682 लोगों ने फॉर्म-7 के जरिए अपने नाम हटाने की अर्जी दी है।

ड्राफ्ट सूची जारी होने से पहले भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। उस समय 16,18,574 लोगों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और 49,399 लोगों ने नाम हटाने के लिए आवेदन किया था। इन सभी आवेदनों को जोड़ने पर नाम जुड़वाने के लिए कुल आवेदन 86 लाख से अधिक और नाम हटाने के लिए तीन लाख से अधिक हो गए हैं।

दावे-आपत्तियों की अवधि समाप्त होने के बाद अब चुनाव आयोग सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग की ओर से नोटिस प्राप्त करीब 3.26 करोड़ मतदाताओं के मामलों की सुनवाई 27 मार्च तक की जाएगी। इसके बाद सभी मामलों का निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसे 10 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 1.04 करोड़ ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है। इसके अलावा लगभग 2.22 करोड़ मतदाताओं के नामों में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित रही है। चुनाव विभाग के अनुसार अब तक भरे गए 84 लाख से अधिक फॉर्म-6 में से केवल 40,643 फॉर्म ही राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से भरवाए गए हैं।

इनमें सबसे अधिक 26,253 फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भरवाए गए हैं। गौरतलब है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। यह प्रक्रिया देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 27 अक्टूबर से शुरू की गई थी।

- प्रदेश में 86 लाख से अधिक लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया।
- 3 लाख से अधिक लोगों ने नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरा।
- 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी।
- दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि 6 मार्च को समाप्त हुई।
- करीब 3.26 करोड़ मतदाताओं के मामलों की सुनवाई 27 मार्च तक होगी।
- 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
- लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं के नाम 2003 की सूची से मेल नहीं खा पाए।
- करीब 2.22 करोड़ नामों में तार्किक विसंगतियां पाई गईं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com